



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार ६ अगस्त, १९९१/१५ आवण, १९१३

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कारण वताओं नोटिस

धर्मशाला-१७६२१५, २९ जून, १९९१

संख्या १८२६-२७.—क्योंकि ग्राम पंचायत चक्रबन्धीण के अंकेशण अवधि ६-८-८० से १५-१-९० में निम्न पंचायत निधि के दुरुपयोग/छलहरण के मालाले साधारण आये हैं :—

(१) प्रधान पंचायत लगातार वर्ष १९८० से अब तक हजारों में पंचायत निधि अपने पास अनाधिकृत रूप से रखकर पंचायत को क्षति पहुंचाते रहे हैं। उसका उल्लेख अंकेशण पत्र के पृष्ठ १८ से २० में है। १/९० को भी प्रधान के पास मु० ५१५५.३० रुपये नकद शेष के रूप में थे। जब आपको दिनांक १०-४-९१ को नकद शेष की राशि जमा करने के लिये कहा तो आपने द्वितीय किया कि मामला अदालत में चला है। नकद शेष की अदायगी पर रोक लगाई गई है। अदालत में चल रहे विवाद की पुष्टि में प्रतिलिपि १७-४-१९९१ तक जिला पंचायत शिक्षिकारी को उत्तरव्य करवाने का विवास दिया था परन्तु आज तक प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि आप वास्तविकता को छुपा कर पंचायत निधि का निरन्तर दुरुपयोग कर रहे हैं।

(२) मीन प्रिंटिंग प्रेस, कांगड़ा से ४५४/- रुपये लेखन सामग्री का क्रय दिखाकर पंचायत रिकार्ड में न स्टाक की वस्तुओं का इन्द्राज पाया गया और प्रयोगक ही पाया गया। इससे स्पष्ट है कि ४५४/- रुपये का छलहरण हुआ है क्योंकि न लेखन सामग्री को प्राप्त ही किया गया है और न ही प्रयोग।

(3) प्राथमिक पाठशाला भवन लौहार लाहडी तथा खप्परनाला का कार्य मार्च 1987 को समाप्त हो गया था तो 31-3-87 को 30 बोरी तथा 20 बोरी तदनुसार क्रय करने का क्या औरित्य था। इस प्रकार (1650 + 1100) मु0 2750/- रुपये का छलहरण किया गया है।

(4) प्रमाणक 6 दिनांक 10-6-85 के अनुसार सर्वश्री रूप लाल मिस्ट्री, अंग्रेज तथा बहादुर सिंह मजदूर के मास 4/85 के मस्ट्रोल संख्या 40 को रद्द करके मस्ट्रोल रजिस्टर संख्या 41 पर पुनः तैयार करके 2, 4 तथा 4 दिन तदनुसार बढ़ाकर मु0 120/- रुपये का छलहरण किया है।

(5) स्लेट के कद्य पर डाला गया मास मार्च 89 में व्यय म0 1000/- रुपये संदिग्ध है क्योंकि प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर नहीं और न ही प्रधान द्वारा रसीद का सत्यापन ही किया गया है।

(6) रसीद संख्या 1 से 62 बुक नं0 7 के अन्तर्गत गृहकर के जनवरी, 1987 में मु0 310/- रुपये प्राप्त किये परन्तु रोकड़ में इन्द्राज जनवरी 1989 को किया गया अर्थात् दो वर्ष तक राशि का दुरुपयोग करते रहे हैं।

(7) वर्ष 1987 में किये गए लौहार लाहडी और खप्परनाला स्कूल के कार्यों पर किये गये खर्च के व्यय के दिनांक को रोकड़ में दर्ज कर्यों नहीं किया गया। बिलम्ब से इन्द्राज करना दुष्भावना का प्रतीक है।

(8) अंकेभण के समय स्टेट बैंक पटिशाला, सहकारी सभा धीण की पास बुके प्रस्तुत न करने पर मु0 1120.11 तथा 1100/- रुपये की राशि को पुष्ट नहीं हो सकी। इससे स्पष्ट होता है कि तथ्यों को छुपाया जा रहा है।

(9) खप्परनाला पाठशाला भवन में तीन खिड़कियों तथा एक दरवाजे के पल्ले नहीं लगाये गये हैं, फर्श नहीं किया गया है। इस प्रकार प्राथमिक पाठशाला भवन लौहार लाहडी में केवल दो दरवाजे के पल्ले लगाए गए हैं और खिड़कियों के पल्ले नहीं लगाये हैं।

(10) श्रीण स्कूल भवन निर्माण में 1274.90 पैसे स्वीकृत अनुदान से अधिक व्यय किये गये हैं।

अतः मैं, बी 0 के 0 अग्रवाल, अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला श्री ज्ञान चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत चकवन्धीण, विकास खण्ड कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) तथा पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस देता हूँ कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों का उत्तर इस पत्र की प्राप्ति के दस दिन के भीतर-भीतर अधिकृताक्षरी को प्राप्त हो जाना चाहिए। यदि विहित अवधि में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जाएगा कि आपको इस विषय में कुछ भी नहीं कहना है और विभाग आपामी आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

बी 0 के 0 अग्रवाल,
अतिरिक्त उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, शिमला, जिला शिमला

अधिकारी

शिमला-1, 22 जुलाई, 1991

संख्या सी0 सी0 एस0 11-15/77-6793-6873.—इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सी0 एस0 11-16/77-6077-6157, दिनांक 25-6-1991 की निरन्तरता में तथा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं

मनाफाखोरी निरीधक आदेश, 1977 की धारा 3 (1) ई के अन्तर्गत प्रदत्त जक्षियों का प्रयोग करते हुए, मैं, पी० सी० ० कपूर, जिन दण्डाधिकारी, शिमला उपरोक्त आदेश की अनुसूची में दर्ज निम्नलिखित वस्तुओं के समस्त करों सहित अधिकतम परचून दरों का निवारण निम्न प्रकार दे करता हूँ:-

श्रावण अनुसूची नं० के अनुसार संख्या	वस्तु का नाम	समस्त करों सहित अधिकतम परचून दर	
1	2	3	4
4.	17.	पका खाना जो ढायें व भोजनालयों में परोसा जाता है :	
	1. पूरा खाना दाल, सब्जी, चावल व चपाती सहित बुराक	8.00 ₹० प्रति बुराक	
	2. स्वीशल सब्जी, राजमाह, चम्बा, गोभी, शिमला मिर्च, पालक, मटर	6.00 ₹० प्रति प्लेट	
	3. मटर पनीर, पालक पनीर	8.00 ₹० , "	
	4. चावल परमल	3.00 ₹० , "	
	5. चपाती तन्दूरी व दूसरी	0.75 ₹० , चपाती	
	6. बीट पकाहुआ	12.00 ₹० , प्लेट	
	7. चिकन करी	14.00 ₹० , "	
	8. दही रायता (200 ग्राम)	3.00 ₹० , "	
	9. दो पूरी सब्जी व दही के साथ	3.00 ₹० , "	
	10. दाल फाइड	3.00 ₹० , "	
	11. परांथा स्टफ़ड	1.50 ₹० , परांथा	
	मिठाई:		
	1. बर्फी, पिस्ता, कलाकन्द	38.00 ₹० प्रति किलो	
	2. बर्फी कोकोनेट	37.00 ₹० , "	
	3. सादी-बर्फी मिल्क केक	37.00 ₹० , "	
	4. लड्डू मोतीचूर	28.00 ₹० , "	
	5. लड्डू मोटा	24.00 ₹० , "	
	6. लड्डू बेसन व बेसन की बर्फी	26.00 ₹० , "	
	7. जलदी	24.00 ₹० , "	
	8. गुलाब जामुन पनीर की मिठाई	36.00 ₹० , "	
	9. बालुशाही, खुरपा, गाजर, मेहसु, पतीका, मुर्गी दाल, पिन्नी, अमरती	26.00 ₹० , "	
	10. सौंत हल्लांगा	36.00 ₹० , "	
	11. मटर नमकोन, सेमियां, मुंगरा दाल, भुजिया	26.00 ₹० , "	
	12. पकौड़ा	24.00 ₹० , "	
	13. समोसा प्रति पीस	1.00 ₹० प्रति पीस	
	14. चाय प्रति कप	1.00 ₹० प्रति कप	
5.	18.	दही :	
	1. दही	10.00 ₹० प्रति किलो	

दुकानदार को दुकान में सहज दृष्टिगत स्थान पर मल्य सची प्रदर्शनत करनी होगी और उस पर दुकानदार/भागीदार/ब्रह्मन्धक के हस्ताक्षर विधि का होमा अनिवार्य है।

यह आदेश हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने के पश्चात सारे शिमला जिला में एक माह की अवधि तक लाग रहेगा।

पी० सी० कूर,
जिला दण्डाधिकारी, शिमला,
जिला शिमला।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4/30 जुलाई, 1991

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (५) १६/७६-१६—अधिसूचना संख्या ३६-८२/७२ पंच-कांगड़ा, दिनांक ६ अक्टूबर, १९७२ को आंशिक रूप से संशोधित करके, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अन्तर्गत जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, १९६८ (वर्ष १९७० का १९३५ अधिनियम) की धारा ४ तथा ५ के अन्तर्गत प्राप्त हैं जिला कांगड़ा के विकास खण्ड नगरोटा बगवां की ग्राम सभा, सिद्धवाड़ी का पुनर्गठन निम्न प्रकार से करने के सहर्ष आदेश देते हैं:—

क्र०	वर्तमान ग्राम सभा कोष्ठ संख्या २ संख्या २	कोष्ठ संख्या २ अपर्वित ग्रामों से बनी कोष्ठ सं० ५ दिवरण सं० का नाम में वर्णित ग्राम में वर्णित ग्राम ग्राम सभा का नाम तथा में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के सभा से अपर्वित उसका मुख्यवास सभा में नाम होने वाले ग्रामों के नाम होने वाले ग्रामों के नाम	वर्णित ग्राम सभा का नाम तथा में वर्णित ग्राम सभा में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम			
१	२	३	४	५	६	७

विकास खण्ड नगरोटा: बगवां

१. सिद्धवाड़ी (सिद्धवाड़ी खास) ।	१. चकबन	—	सिद्धवाड़ी (सिद्धवाड़ी खास) ।	कोष्ठ सं० ३ में वर्णित सभी गांव तथा योल कैट से निकाले गए ग्राम १. छेहडू	वर्तोंकि ग्राम ठेहड़ तथा गांव तथा योल छतैड़ योल लावनी से गए ग्राम और इन्हें निकाले वर्ती ग्राम सभा सिद्धवाड़ी में मिलाया जाना अवश्यक है।
	२. बाधनी			२. बाधनी	
	३. सिद्धवाड़ी खास ।			३. सिद्धवाड़ी खास ।	
	४. रकड़			४. रकड़	
	५. रसी			५. रसी	

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

सचिव ।

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 4 जूलाई, 1991

संख्या पी० सी० ०६० एच०-एच० ६० (५) ३६/९१।—क्योंकि श्री बलवत् सिंह, निवासी गांव व डाकघर संधोट, जिला मण्डी की शिकायत पर प्रधान, ग्राम पंचायत संधोट, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी पंचायत निवास व शवन का कीमती सामान लकड़ी, स्लेट आदि को खुद-बुद्ध करने में मनिष्ठ पाए गए हैं।

यह कि इस मामले में विभाग द्वारा प्रारम्भिक जांच करवाई गई तथा निम्न मुद्रे उभरे हैं:—

1. यह कि पंचायत घर का छत उखाड़ कर उसका जो सामान स्लेट $9 \times 18'' = 2450$ काठों = 30 पीपल (10×10) गज 170 पीपल (4×5) तथा मिलिंग पट्टी 122 कापल आदि की प्रधान पंचायत ने नीलामी की और 70.69/- रुपये प्राप्त किए परन्तु न तो छत उखाड़ने की अनुमति ली और न ही नीलामी किए जाने की स्वीकृति एवं नीलामी सम्बन्धी रिकाउं रखा जिसमें सामान खुद-बुद्ध करने को नाकारा नहीं जा सकता।

2. यह कि भवन की दिवारों की मुरम्मत करके बीम व स्टीब डाला गया जिसके लिए न तो तकनीकी विशेषज्ञ की राय ली गई और न ही स्टीब डालने से पहले सरिये, सीमेंट लगाने की तकनीकी सलाह ली गई। भवन की नींव भी पक्की नहीं की गई।

3. यह कि भवन ठेका श्री रोशन लाल पुत्र खजाना को मूँ 60,000 रुपये में विना टैंडर बुलाये व तकनीकी सलाह लिए दिया गया जिसमें 52,000 हजार नकद देना था और 8,000/- रुपये का नीलामी का सामान। उस व्यक्ति को 2,600/- रुपये पेशगी जो बाद में वापिस लेकर 33,063-59 का सामान ईंटे, रित, बजारी क्रय किया गया तथा नीलामी का 7,069 रुपये का सामान भी दिया गया इसके लिए मूँ 25,000/- रुपये उपायुक्त से मुरम्मत के लिए स्वीकृत थे और 25,000/- जवाहर रोजगार योजना के अधीन खण्ड विकास अधिकारी से राशि ली गई जिसमें से मूँ 022,000/- रुपये रोशन लाल को पेशगी में दिए गये। इस बारे न कोई प्लान, एस्टीमेट बनाया गया न ही प्रशासकीय स्वीकृति लो गई और क्योंकि उपरोक्त मामले में वास्तविकता जानने के लिए नियमित जांच का करवाया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) के अधीन उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक), सरकारी घट, जिला मण्डी को जहाँ जांच अधिकारी नियुक्त करने का आदेश देते हैं। वह अपनी जांच रिपोर्ट उपायुक्त, मण्डी के माध्यम से शीघ्र प्रस्तुत करेंगे। वह अधीक्षक ग्रेड-2 कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, धर्मपुर (मण्डी) को प्रस्तुत कर्ता नियुक्त करते हैं जो जांच के दोरान सरकार का पक्ष भी प्रस्तुत करेंगे।

हस्ताक्षरित/
अधर सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-५ द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।